RAJYA SABHA

Friday, the 26th My, 1996/4 Srava-na, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the Clock. [the Deputy Chairman *in the chair.]*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दानापुर रेलवे कालोनी की दयनीय हालत

*241. श्री नागमणि: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दानापुर की रेलवे कालोनी में मरम्मत कार्य न होने के कारण इस कालोनी की हालत काफी दयनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी नहीं, दानापुर स्थित रेलवे कालोनी का समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अनुरक्षण किया जाता है;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री नागमणि: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दानापुर रेलवे कालोनी की स्थिति काफी जर्जर है, मकानों की छत टूट गई है जिससे बरसात के दिनों में घर के अन्दर पानी खड़ा हो जाता है। क्या मंत्री जी दानापुर रेलवे कालोनी के मकानों की मरम्मत शीघ्र से करवायेंगे?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति, महोदया, दानापुर में कुल मिलाकर दो तरह के क्वार्टर्स हैं एक जो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के क्वार्टर होते है ये अच्छे होते हैं और दूसरे क्वार्टर्स जिनको सब-स्टैन्डर्ड कहते हैं ये क्वार्टर्स दानापुर में 220 थे और उनमें से 170 क्वार्टर्स में तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 59 क्वार्टर्स उसी हालत में हैं। उन क्वार्टर्स के सुधार के लिए आदेश दे दिये गये हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है हमने अनुसार वहां दुबारा जांच करवाई है और जांच के बाद पता चला है कि बरसात के कारण वहां जल का जमाव है और रोड की हालत भी अच्छी नहीं है। हमने जांच के आदेश फिर दे दिये हैं। सीनियर आफिसर्स को कहा है कि आप स्वयं जाकर वस्तुस्थिति का पता लगायें। वहां कांट्रेक्टर्स काम करते हैं इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी रह जाती है। हमने कहा है कि चाहे दोषी कांट्रेक्टर हो, पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपसभापति: गया सिंह जी आप सेटिसफाइड हैं?

श्री गया सिंह: माननीय उपसभापति जी, मंत्री जी ने जांच भी करवाई है और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं। लेकिन इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि दानापुर की रेलवे कालोनी बिहार का एक ऐसा उदाहरण है जहां रेलवे इम्पलाइज के सब-स्टैन्डर्ड क्वार्टर्स ज्यादा हो गये हैं और जो आफिसर्स हैं उनके लो ए और बी ग्रेड के क्वार्टर्स हैं उनमें तो सुधार है लेकिन जो खासतौर से थर्ड ग्रेड इम्पलाइज के क्वार्टर्स हैं, जिनको मंत्री जी ने सब-स्टैन्डर्ड कहा है, उनकी स्थिति दानापुर में खराब है और बिहार में दूसरी रेलवे कालोनीज में भी खराब है, इस पर मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, यदि फंड की कमी हो तो उसे बढ़ाया जा सकता है लेकिन जहां तक हमने देखा है पिछले तीन सालों में दानापुर को जो पैसा दिया गया है उसके मुताबिक 1995-96 में 41.51 लाख रुपये दिया गया है इसके अलावा 46.43 लाख रुपया दरवाजे, छतों के मरम्मत, विद्युत आदि के लिए दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा पूरे देश में अभी जो क्वार्टर्स हैं उनकी संख्या 6 लाख 30 हजार है। उस 6 लाख 30 हजार में से जो सब-स्टैंडर्ड क्वार्टर्स हैं वे 85 हजार हैं और उन 85 हजार को दस साल के अंदर सुधार लिया जाए। माननीय सदस्य यह भी पूछ सकते हैं जो सब स्टैंडर्ड क्वार्टर्स हैं उनके आप क्यों रखे हुए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के पास संसाधनों का अभाव रहता है और उसके अनुसार ही हम लोग उनकी मरम्मत करके, जब तक चलती है चलाने का काम करते हैं। यह बात सही है कि इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने अधिकारियों से कहा है कि यदि इसमें फंड की कहीं कमी हो तो उसके लिए हम फंड देने के लिए तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य यह भी कहेंगे कि हाई क्लास श्रेणी के क्वार्टरों में ऐसा नहीं है। यह सही है कि जहां कहीं भी यह होता है, उसमें जो कर्मचारी परेशान होता है, वह निचली श्रेणी का कर्मचारी होता है। यह भी हमने

कहा कि आप पता लगायें। दानापुर ए और बी ग्रेड में जो टाइप "I" है वह 1122 क्वार्टर्स है, टाइप "II" जो हैं वह 954 है। तीसरी श्रेणी के 102 है और चौथी श्रेणी के भी 124 है। पांचवीं श्रेणी के जो हैं वे 26 हैं। तो हमने यह भी पता लगाने के लिए कह दिया है कि तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइप "IV" व "V" क्लास वन के जो क्वार्टर है उनको बढ़िया तरीके से सजाकर तो नहीं रखा गया है और क्लास थ्री और क्लास फोर के जो कर्मचारी है उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस बारे में चिन्तित हूं। मैं श्री नागमणि जी का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने इस प्रश्न को यहां उठाने का काम किया है। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की जब शिकायतें आयेंगी तो उसमें जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी हम उसकी कड़ाई से जांच करेंगे और दोषी लोगों के खिलाफ, वह जो भी होगा, चाहे कांट्रेक्टर हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

उपसभापति: श्रीमती कमला सिन्हा, आप अब भी पूछना चाहेंगे। अगर स्पेसिफिक हो तो ....

श्रीमती कमला सिन्हा: मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या वे सब-स्टैंडर्ड क्वार्टर बिहार में ही हैं या बिहार के बाहर भी है? अगर बिहार के बाहर भी हैं तो जो मंत्री जी ने आदेश दिया है वह पूरे विभाग के लिए है या केवल यह आदेश उनके अपने प्रान्त के लिए है?

उपसभापति: कमला सिन्हा जी, यह केवल बहुत ही स्पेसिफिक दानापुर के बारे में है। मंत्री जी ने इसका रिप्लाई दे दिया।

श्रीमती कमला सिन्हा: वह मैं जानती हूं कि उन्होंने व्यापक रूप से बिहार के बारे में कहा है। इसीलिए मैंने यह पूछा है। मैं जानना चाहता हूं कि सब-स्टैंडर्ड मकान क्यों रखे गए हैं और यह किन के लिए हैं। आज भी इतने सब-स्टैंडर्ड मकान रेलवे इम्प्लाईज के लिए है यह बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए मैं चाहता हूं, राम विलास भी शोषित, पीड़ित और दलितों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। इसलिए उनसे मेरी अपेक्षा है कि यह सब-स्टैंडर्ड मकान, जिनमें क्लास फोर और क्लास थ्री कैटेगरी के लोगों को मजबूरी में रहना पड़ता है, उनको सुधारेंगे और उनको भी ह्यूमन बिइंग के तौर पर रहने के लिए क्या वे कुछ उपाय करेंगे, यह मैं उनसे जानना चाहती हूं?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, मैंने कहा कि अभी पूरे देश में 85 हजार ऐसे सब-स्टैंडर्ड क्वार्टर्स हैं और पूर्व रेलवे में 5613 है और दानापुर में 229 थे जिनमें से केवल 59 बचे हैं। लेकिन आपने जो पूछा तो जब हम नीति बनाते हैं, पूरे देश के लिए हम नीति बनाते हैं। हमने जो खर्चा किया है, इसके पूरे देश के आंकड़े हमारे पास हैं। अगर आप चाहती है तो मैं उन आंकड़ों को भी बता सकता हूं। लेकिन इससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये जो मकान है इनसे निपटने के लिए हर स्तर पर हम कौन से कदम उठायें यह जो करप्शन व्याप्त है, यह उस करप्शन का एक अंग है और इसको स्वीकारने में हमें कोई हिचक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि वहां गड़बड़ी नहीं हो रही है और यह गड़बड़ी पूरे देश में, जहां जहां यह है, वहां नहीं होती होगी। लेकिन जहां जहां से हमारे पास शिकायतें आई हैं, सब जगहों पर हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां जहां सब-स्टैंडर्ड क्वार्टर्स हैं, वहां हम कोशिश करते हैं कि उनको बदला जाए। लेकिन एकाएक सब को बदलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। इसलिए हमने कहा कि सौ, दो सौ सब-स्टैंडर्ड क्वार्टर बदल दें। हम उनको धीरे-धीरे बदलेंगे। हमने कहा भी है कि अगर राशि की कमी होगी तो हम इसके लिए राशि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उनकी दयनीय स्थिति है उसमें सुधार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अगर कहीं उनके पास और भी कोई शिकायत आए तो हमको तुरन्त सूचित करने का काम करें जिससे हम उसकी इमीजिएट जांच करवा सकें।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभापति महोदया, दानापुर डिविज़न ब्रिटिश साम्राज्यवाद से चलता आ रहा है और यहां की जो रेलवे कालोनी है, ब्रिटिश जमाने की बनी हुई है और उसी पर प्लास्टर और पेंट चल रहा है। इसकी फाउंडेशन खराब हो चुकी है। उस टाइम उस इलाके का वाटर लैवल इतना हाई नहीं था जिसके कारण वहां मकानों की अवस्था इतनी खराब नहीं थी। अब दिन प्रतिदिन वहां के मकानों की अवस्था खराब हो गई है। इस तरह से और भी डिविज़न हैं जहां ब्रिटिश टाइम की कालोनियां बनी हुई हैं। हर एक घर की अपनी लाइफ होती है और यह मकान अपनी लाइफ को पार कर चुके हैं। इसके बावजूद भी रंग-रोगन कर के प्लास्टर कर के काम चलाया जा रहा है। अगर घर में घुसियेगा तो देखियेगा कि इतनी ह्युमिडिटी और सड़ाम है कि वहां आदमी जानवर से भी बदतर हालत में रह रहे

हैं। उन मकानों को तोड़ कर उनकी जगह पर नये मकान बनाने का क्या आपने कोई प्लान बनाया है? क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो मकान बने हुए हैं सन् 1932 से 1940 में यह मकान बने थे, उनको तोड़ कर नये सिरे से मकान बनाने का आपने प्लान बनाया है?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, मैं ने अभी यह कहा कि इस तरह के पूरे देश में 30 हजार घर हैं और इन 30 हजार मकानों को एकाएक तोड़ दें तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि उनकी जगह नये मकान बना कर हम दे सकें। इसलिए मैंने कहा कि हम सुधार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया 229 थे और अब 59 इस तरह के हैं। हमें यह भी पता चला है कि कुछ छतें ऐसी हैं जो चू रही हैं। हालांकि हम लोगों की छतें चूने लगती हैं (व्यवधान) लेकिन वहां की छत का चूना लापरवाही का द्योतक है। हम कोशिश कर रहे हैं यदि ऐसा कोई मकान हो जो बिलकुल रहने लायक नहीं हो, टूटने वाला है, टूट जाएगा तो उसके बदले में नया मकान बनाया जा सकता है लेकिन मैं अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि जितने भी पुराने मकान हैं उनको तोड़ कर उनकी जगह नये बना कर हम दे देंगे।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः फेड़वाइज़ करिये।

उपसभापतिः श्री मोहम्मद सलीम। इतने विस्तार से जवाब मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री मोहम्मद सलीमः उपसभापति जी, मंत्री महोदय अपने जवाब में जो जनरल समस्या है, उस पर चले आए हैं कानपुर से बाहर निकल कर। बात यह है कि तमाम रेलवे कालोनीज़ में पुराने किस्म के मकान हैं। उनका लैंड यूटीलाइजेशन भी बहुत साइंटिफिक नहीं है। उस समय काफी जमीन मिलती थी। हकूमत से लैंड एक्वायर कर के बंगला टाइप के मकान बना दिये गये अभी जो मकान बनाने जा रहे हैं उस पर मेंटेनेंस पर खर्च नहीं करके क्या हम शहरी क्षेत्रों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। मैं कलकत्ता में देखता हूं साऊथ ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर है। मेरा सुझाव यह है कि आप जब भी नये मकान बनाएं, बंगला बनाने के बजाय आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएं ताकि कम से कम जगह पर ज्यादा लोगों को बसाया जा सके। मकान अक्सर ऐसी जगह होते हैं कि आप सभी इंपलाइज़ को मकान दे नहीं पाते हैं। जिनका आप ट्रांसफर करते हैं आप्रेशन के लिए अक्सर ही होता है लेकिन सिर्फ मकान के लिए लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनको वहां मकान नहीं मिलता है। इससे आपका जो आप्रेशन है, वह अफेक्ट होता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंगें ही बनायेंगे ताकि ज्यादा लोगों को मकान मिल सके और जमीन का भी साइंटिफिक यूटीलाइजेशन हो सके?

†[]डाक्टर मोहम्मद सलीम: उपसभापति जी, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो जनरल सिम्पैथी है उसपर चले आए हैं कानपुर से बाहर निकल कर। बात यह है कि तमाम रेलवे कालोनीज में पुराने किस्म के मकान हैं। उनका लैंड यूटीलाइजेशन भी बहुत साइंटिफिक नहीं है। उस समय काफी जमीन मिलती थी। हकूमत से लैंड एक्वायर कर के बंगला टाइप के मकान बना दिये गये अभी जो मकान बनाने जा रहे हैं उस पर मेंटेनेंस पर खर्च नहीं करके क्या हम शहरी क्षेत्रों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। मैं कलकत्ता में देखता हूं साऊथ ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर है। मेरा सुझाव यह है कि आप जब भी नये मकान बनाएं, बंगला बनाने के बजाय आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएं ताकि कम से कम जगह पर ज्यादा लोगों को बसाया जा सके। मकान अक्सर ऐसी जगह होते हैं कि आप सभी इंपलाइज़ को मकान दे नहीं पाते हैं।

†[]Transliteration in Arabic Script.

†[श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहब, मैं आपके ज़रिये से मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ भी करना चाहूंगा और सवाल भी पूछना चाहूंगा। सवाल दानापुर से निकल कर तमाम रेलवे के मातहत जितने पुराने मकानात हैं, उन तक पहुंच गया है और एक तरह से यह सोचा जाए तो पॉलिसी का भी सवाल आ गया है। जो मकानात पुराने हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी खत्म कर चुके हैं उनको मेनटेन किये जाने का सवाल है। अब अहलुवालिया साहब के जवाब में जो मंत्री जी ने कहा वह दुरुस्त नहीं है। जब इन्होंने बात की थी तो आप प्रेजुयली ठीक करना शुरू कीजिये, नये मकानात बनाइये। एकदम सारे मकानात गिरा कर उनकी जगह नये मकानात बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजे बिलकुल अहम हैं। आज लोग ज्यादा हैं तो जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी हो और इन मकानात की मेंटेनेस में इतना ज्यादा खर्च न होने लगे कि असल कीमत से, तामीर की कीमत से मेंटेनेंस की कीमत बढ़ जाए। यह सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, दानापुर में नहीं हो रहा है, दानापुर के बाहर रेलवे कालोनीज में अलग हो रहा है।

†شری سکندر بخت: صدر صاحب۔ میں آپکے ذریعہ سے منسٹر صاحب کی خدمت میں عرض بھی کرنا چاہونگا اور سوال بھی پوچھنا چاہونگا۔ سوال دانا پور سے نکل کر تمام ریلوے کے ماتحت جتنے پرانے مکانات ہیں ان تک پہنچ گیا ہے اور ایک طرح سے یہ سوچا جائے تو پالیسی کا بھی سوال آگیا ہے۔ جو مکانات پرانے ہو چکے ہیں جو اپنی زندگی ختم کر چکے ہیں انکو "مینٹین" کئے جانے کا سوال ہے۔ اب آہلووالیہ صاحب کے جواب میں جو منتری جی نے کہا وہ درست نہیں ہے۔ جب انھوں نے بات کی تھی تو آپ "گرتجوی" پرانے مکانات کی جگہ جنکی "مینٹینس" انکے بننے کی قیمت سے زیادہ ہو رہی ہے انکو "گرتجوی" ٹھیک کرنا شروع کیجیے۔ نئے مکانات بنایئے۔ ایکدم سارے مکانات گرا کر انکی جگہ نئے مکانات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں چیزیں بالکل اہم ہیں۔ آج لوگ زیادہ ہیں تو زمین کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی ہو اور ان مکانات کی "مینٹینس" میں اتنا زیادہ خرچ نہ ہونے لگے کہ اصل قیمت سے۔ تعمیر کی قیمت سے "مینٹینس" کی قیمت بڑھ جائے یہ صرف آپکے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ دانا پور جنکا آپ نے سروے کرتے ہیں کیونکہ جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو انکو وہاں مکان نہیں ملتا ہے اس سے آپکا جو آپریشن ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے میں منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ ہی بنائینگے تاکہ زیادہ لوگوں کو مکان مل سکیں اور زمین کا بھی سائنٹیفک یوٹیلائزیشن ہو سکے۔]

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, अभी तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मल्टी स्टोरीड बनायेंगे लेकिन जहां कहीं भी मकान बनायेंगे, अच्छे मकान बनायेंगे और ठीक-ठाक तरीके से जमीन को देख कर कि जल का जमाव नहीं हो, सारी चीजों को देख कर बनायेंगे। यदि जमीन की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि मल्टी स्टोरीड क्वार्टर बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं लेकिन इस संबंध में मैं आपको बाद में सूचना दे दूंगा।

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहेबा, मैं आपके ज़रिये से मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ भी करना चाहूंगा और सवाल भी पूछना चाहूंगा। सवाल दानापुर से निकल कर तमाम रेलवे के मातहत जितने पुराने मकानात हैं, उन तक पहुंच गया है और एक तरह से यह सोचा जाए तो पॉलिसी का भी सवाल आ गया है। जो मकानात पुराने हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी खत्म कर चुके हैं उनको मेनटेन किये जाने का सवाल है। अब अहलुवालिया साहब के जवाब में जो मंत्री जी ने कहा वह दुरुस्त नहीं है। जब इन्होंने बात की थी तो आप प्रेजुयली ठीक करना शुरू कीजिये, नये मकानात बनाइये। एकदम सारे मकानात गिरा कर उनकी जगह नये मकानात बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजे बिलकुल अहम हैं। आज लोग ज्यादा हैं तो जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी हो और इन मकानात की मेंटेनेस में इतना ज्यादा खर्च न होने लगे कि असल कीमत से, तामीर की कीमत से मेंटेनेंस की कीमत बढ़ जाए। यह सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, दानापुर में नहीं हो रहा है, दानापुर के बाहर रेलवे कालोनीज में अलग हो रहा है।

†[ ] Transliteration in Arabic script.

میں نہیں ہو رہا ہے۔ ڈانابور سے باہر
ریلوے کالونیز میں الگ ہو رہا ہے۔

और हिंदुस्तान भर में गलत रास्ते पर चला जा रहा है। क्या रेलवे मिनिस्टर साहब यह कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट के मकानात है, उनमें जितने मकानात पुराने हो चुके हैं, उनकी जगह धीरे-धीरे नये मकान बने और आप्टीमम लैंड यूज हो?

†مشری سکندر بخت "جاری": اور ہندوستان
بھر میں غلط راستے پر چلا جا رہا ہے۔ کیا ریلوے
منسٹر صاحب یہ کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ
کے مکانات ہیں۔ ان میں جتنے مکانات
پرانے ہو چکے ہیں ان کی جگہ دھیرے دھیرے
نئے مکان بنیں اور "آپٹیمم لینڈ" یوز ہو۔

श्री राम विलास पासवान: मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं और मुझे लगता है कि कुछ मकान हैं जो नये बनाये जा रहे हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा। इन्होंने कहा कि जो लार्ज सिटीज में बिल्डिंग्स बन रही हैं वे मल्टी-स्टोरीज बन रही हैं। इसलिए जो फेजवाइज में करने की बात है, हम इस बात को करेंगे।

Completion of Konkan Railway Project

*242. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the details of completion of Konkan Railway Project and what is the total cost of the project as per the present estimate; and

(b) by when Konkan Railway Project will be completed and commissioned?

(रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 760 कि०मी० में से अभी तक 229 मार्ग किलोमीटर लाइन को यात्री यातायात के लिए खोला गया है और अन्य 460 कि०मी० लाइन लगभग तैयार है। मार्च, 1996 के अनुमान के अनुसार इस परियोजना की लागत 2230.42 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, कोंकण रेलवे को दिसंबर, 1996 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam Deputy Chairman, this 760 km. single track Konkan Railway Project comprises 382 kms. in Maharashtra, 273 kms. in Karnataka, and 105 kms. in Goa. This project has 145 major bridges and 1670 minor bridges. It also has 81 tunnels; the length of the largest tunnel is 6.5 kms. These tunnels pass through a difficult terrain. In fact, Madam, this project is a challenge to the expertise of our planners and engineers.

The Konkan railway line passes through three States. A number of industries are coming up, worth about Rs.50,000 crores. In Karnataka alone, in my district, i.e. Dakshina Kannada, a number of projects—steel plants, power projects and refineries—are coming up. The entire nation is waiting for the speedy completion of this prestigious project.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it looks as if he is replying to the question as a Minister.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam, the original deadline fixed for the completion of this project was March, 1994. It was extended and another deadline was fixed, i.e. December, 1995. The hon. Minister, while presenting the Railway Budget on 16th July, 1996, fixed the' deadline for the inauguration of traffic as October, 1996. However, Mr. Minister, in the reply giyen today, within a matter of ten days, your Department has changed the deadline. You now say that it will opened for traffic in the month of December, 1996. You say that you have difficulties; financial as well as technical. May I know from the hon. Minister whether, in regard to finance, he has tied up with the Planninng

†[ ] Transliteration in Arabic script.